*रोम के ट्रैवी फाउन्टेन में हर साल दस लाख यूरो से ज्यादा मूल्य के सिक्के फेंके जाते हैं। सन् 1762 में बना मार्बल का यह अद्भुत नमूना रोम के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। परम्परा के अनुसार यहाँ आने वाले पर्यटक फाउन्टेन की तरफ पीठ करके दाहिने हाथ से बाएं कंधे के ऊपर से सिक्का उछालते हैं। मान्यता है कि, ऐसा करने से इस जगह वापस आने का मौका मिलता है। यह परम्परा 1954 में आई एक फिल्म ''थ्री कॉइन्स इन द फाउन्टेन'' की देन है। फिल्म में, रोम में रह रही तीन अमेरिकन महिलाएं रोम में अपना प्यार पाने की कामना से फाउन्टेन में सिक्के डालती हैं। फाउन्टेन में डाले गए सिक्कों को सक्शन मशीन से बाहर निकाला जाता है। कैरिटास नामक एक चैरिटी संख्या, जो कैथलिक चर्च द्वारा संचालित है, इन सिक्कों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है। इन पैसों से गरीबों के लिए नर्सिंग होम, कैन्टीन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। बताया जाता है कि, ईसापूर्व उन्नीसवीं सदी में इस एक्वाडक्ट का नाम ट्रैवी नाम की एक खूबसूरत युवती के नाम पर रखा गया था, जो प्यासे सैनिकों को इसी स्थान पर मौजूद एक चश्मे के पास ले जाती थी। यह एक्वाडक्ट रोम और इसके अनेक स्नानागारों का मुख्य जल स्रोत था और इसी के ऊपर बाद में फाउण्टेन बना है। फाउण्टेन के बीच में सी हॉर्सेज़ के रथ पर सवार एक देवता की भी मूर्ति है। रोम के इतिहास में नैप्च्यून मीठे पानी के देवता हैं इसलिए माना जाता था कि, यह अवश्य ही नैपच्यून की मूर्ति होगी। परंतु यह ग्रीक गॉड ओशनस की मूर्ति है, जो यूनानी मायथॉलजी के अनुसार समुद्र का देवता है। इसके चारों तरफ सीहॉर्स और जलपरियों की मूर्तियाँ हैं। निकोला साल्वी द्वारा डिज़ाइन किए इस फाउण्टेन का निर्माण सन् 1732 में शुरु हुआ और 1762 में पूरा हुआ। यह फाउण्टेन अनेकों फिल्मों में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ छेड़खानी की कोशिश भी हुई है। सन् 2007 व 2017 में इटली के एक एक्टिविस्ट ने भ्रष्टाचार के विरोध में फाउण्टेन के पानी में लाल रंग डाल दिया था। सन् 2012 में कड़ाके की ठंड की वजह से फाउण्टेन क्षतिग्रस्त हो गया था तब जून 2014 में फाउण्टेन को बंद करके इसकी मरम्मत की गई और जून 2015 में इसे पुनः शुरु किया गया।*

# पार्टी का सारा काम संगठन महामंत्री की मर्जी से होने की चर्चा

## प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित?

- **चर्चा है कि, प्रदेश भाजपा में प्रदेश संगठन महामंत्री सर्वेसर्वा की भूमिका में आ चुके हैं, जो लगभग 6 वर्षों से संगठन महामंत्री हैं, जिनकी मर्जी के बिना अब पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है।**
- **चर्चा में हैं कि, चंद्रशेखर का पार्टी के वित्तीय प्रबंधन में पूरा दखल था ही, साथ ही पार्टी के तमाम फैसलों में भी काफी दखल रहा, लेकिन मौजूदा हालात में संगठन महामंत्री इतने हावी हो गये हैं कि, पार्टी के हर फैसले में पूरा दखल कर लिया है, किसी की कुछ कहने, करने और आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे में पूरी प्रदेश भाजपा मौन रहती है।**

जयपुर, 28 अप्रेल (का.सं.)। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में इन दिनों एक चर्चा जोरों पर हैं कि भाजपा में संगठन महामंत्री के बिना पत्ता भी नही हिलता है। कई कार्यकर्ता तो अपनी दबी हुई जबान से ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर ही भाजपा हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के झंडे बैनर, होर्डिंग्स, प्रिंटिग कार्य, अभियानों के बैनर जो भी सामग्री तैयार होती है, उनके टेंडर देने में संगठन महामंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका की है। पार्टी के जिलों में जो कार्यालय बने और बनने वाले कार्यालयों के निर्माण कार्य, जमीन फाइनल करने से लेकर इत्यादि कार्यों में संगठन महामंत्री की टीम का ही प्रबंधन और निर्णय महत्वपूर्ण रहता है। अब कार्यकर्ताओं ने दबी आवाज से कह रहे हैं कि जयपुर में बनने वाले प्रदेश कार्यालय की जमीन देखने से लेकर और उसके निर्माण में लगने वाले बड़े बजट की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसमें संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की कितनी भूमिका रहती है।

यहां तक कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 से लेकर लगभग फरवरी 2023 तक भाजपा जन आक्रोश यात्रा के लिये जिस एजेंसी से रथ मंगवाये गये थे, वह राजस्थान से बाहर की है। इनमें से काफी संख्या में रथ दिल्ली और उत्तरप्रदेश के नंबरों के थे। अब एक नई चर्चा और है कि भाजपा द्वारा राजस्थान के ट्विटर और फेसबुक पेजों को हैंडिल करने के लिये काफी महीनों पहले ही एक एजेंसी हायर की गई, और वह भी उत्तरप्रदेश की है। कार्यकर्ताओं का कहा है कि संगठन महामंत्री चंद्रेशखर की कार्यशैली से राजस्थान में संघ काफी नाराज है। कार्यकर्ता कहते हैं कि इनकी कार्यशैली की शिकायत पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। प्रदेश भाजपा में ओबीसी, दलित और जनजाति वर्ग पूरी तरह साइडलाइन हो गया हैं। दिल्ली के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के बारे में केन्द्रीय नेतृत्व को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें भी इन बड़े समुदायों का वोट बैंट भाजपा से दूर खिसकने का संकेत दिया गया है।

भाजपा संगठन के सर्वेसर्वा बने चंद्रशेखर के सामने मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर पार्टी के मोर्चा और प्रदेश की टीम में परिवर्तन करने की जल्दी में हैं, ऐसे में चर्चा है कि कहीं उन्हें खुद को बदले जाने का संकेत मिल गये हैं?

पार्टी प्रदेश कार्यालय की अंदरूनी हकीकत की बात करें तो संगठन महामंत्री ने अपने कई खास लोगों को पार्टी प्रबंधन से जुड़े पदों पर बिठाया है, जो भाजपा प्रदेश कार्यालय के प्रबंधन में पूरा दखल रखते हैं, जिनके आगे प्रदेश पदाधिकारी भी मौन रहते हैं।

राजस्थान संगठन में तीन बड़े पदों पर बैठे लोगों के जातिगत-सामाजिक संतुलन की बात करें तो प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ब्राह्मण, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजपूत है, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी राजपूत हैं। ओबीसी-किसान, दलित और जनजाति वर्ग का संगठन के इन तीन बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व नही होने की चर्चा है, और यह बात गांव-ढाणियों तक फैलती जा रही है, जिसका विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। जनाक्रोश सभाओं में कम लोगों का आना भी चर्चा का विषय बन गया है।

## 'मेरी मां ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

के स्ट्रोक धीरे-धीरे उबर रही हैं। सिंह की लापरवाही और उपेक्षा इससे और भी पुष्ट होती है कि उन्होंने जयमाला को अपनी बहिन के घर भेज दिया था।''

एक बयान में उन्होंने कहा, मैं ऐसा अकेला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी माँ के दाह संस्कार को लम्बित करने तथा उनके शव को मुरदा घर में सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है। ऐसा करने का कारण यह तथ्य है कि जनवरी 2022 में मेरी श्रीनगर की अंतिम यात्रा के बाद, भारत सरकार ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसके बाद 13 फरवरी 2022 को मुझे ब्रिटिश पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब मैं जम्मू-कश्मीर की जनता की खातिर भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर रहा था।''

अंकित ने आगे कहा, ''मैं लंदन-स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव से व्यक्तिश: मिला हूँ तथा उनसे कहा है कि वे मुझ पर लगे प्रतिबंध रद्द करा दें तथा वे ऐसा कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।''

# कूनो के कुछ चीतों को राजस्थान के मुकुंदरा में स्थानांतरित करने पर विचार

## कूनो में एक माह के अंतराल में दो चीतों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कुछ चीतों को दूसरे स्थान पर भेजने की चर्चाएं तेज हो गई हैं

- **पिछले माह मार्च में हुई चीता टास्कफोर्स की बैठक में राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य में कुछ चीतों को शिफ्ट करने पर विचार विमर्श हो चुका था।**
- **इसमें मुकुंदरा उद्यान प्राथमिकता पर रखा गया था और यहां पर चीतों को बसाने के लिये सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं।**

मुरैना, 28 अप्रेल। मध्यप्रदेश में चंबल संभाग के श्योपुर जिला स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाये गए चीतों को अब राजस्थान के मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरण करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

वन विभाग के एक आला अधिकारी के अनुसार हाल ही में एक माह के अंतराल में कूनो में दो चीतों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कुछ चीतों को दूसरे स्थान पर भेजने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वन विभाग ने 24 अप्रेल को राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण (एनटीसीए) को एक पत्र लिखकर चीतों के लिये वैकल्पिक स्थान की मांग भी की है।

सूत्रों का कहना है कि, कूनो के कुछ चीतों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना पहले से ही प्रस्तावित था। पिछले माह मार्च में हुई चीता टास्कफोर्स की बैठक में राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य में कुछ चीतों को शिफ्ट करने पर विचार विमर्श हो चुका था। बैठक में सामने आया कि कूनो से कुछ चीतों को तत्काल भी शिफ्ट किया जाए तो मुकुंदरा हिल्स पूरी तरह से तैयार है।

वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि, दक्षिण अफ्रीका के चीतों के लिये राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स उद्यान के साथ ही मध्यप्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य को चिन्हित किया गया था। इसमें मुकुंदरा उद्यान प्राथमिकता पर रखा गया था और यहां पर चीतों को बसाने के लिये सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। वहीं गांधी सागर में व्यवस्थाएं जुटाने में करीब एक साल का समय भी लग सकता है। हालांकि कूनो से कितने चीते कब शिफ्ट होंगे ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना हैं।

सूत्रों ने कहा कि, मध्यप्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जेएस चौहान ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण (एनटीसीए) को पूर्व में एक पत्र भी लिखा था जिसमें उनके विभाग ने चीतों के लिये वैकल्पिक स्थान का आग्रह किया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के 748 वर्ग किलोमीटर में अधिकतम 20 से 21 चीतों को रखने की क्षमता है। इस लिहाज से 18 चीतों के लिये अभी पर्याप्त स्थान हैं। इसके लिये चीतों की संख्या कम करने की जरूरत है।

## 'अगर शिकायत...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

था कि वह हेट स्पीचेज़ के विरूद्ध कार्रवाई करने में विफल रही है।

जस्टिस के.एम. जोसफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की डबल बैंच ने आज अपने एक आदेश में कहा कि ''हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि हेट स्पीच देने वाले के धर्म का लिहाज ना करते हुए एक्शन लिया जाए, जिससे कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का संरक्षण किया जा सके।

याचिकाकर्ताओं ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल ऑफीसर नियुक्त किया जाए। इस पर बैंच ने प्रत्येक जिले में एक नोडल ऑफीसर का सुझाव दिया। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि हेट स्पीच को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया तय करने की जरूरत है।

हेट स्पीच को लेकर केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की याचिका में की गई मांग पर जस्टिस के.एम. जोसफ ने कहा कि इस बारे में लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने माना था कि मंत्री के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है और हाई कोर्ट का भी ऐसा मानना था कि 156 (3) के लिए अनुमोदन जरूरी है।

बैंच ने कहा कि ''जजों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तथा वे किसी ''ए'' अथवा ''बी'' पार्टी से संबंधित नहीं है। उनके ध्यान में एक ही बात रहती है और वह है भारत का संविधान।''

उसने कहा कि कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों में हुईं हेट स्पीचेज़ के विरूद्ध दायर याचिकाओं पर जनता की भलाई और कानून का राज सुनिश्चित करने को लेकर सुनवाई करता रहा है। विधि सम्मत शासन के प्रति जनता के विश्वास की बहाली को लेकर आज के आदेश का दीर्घकालीन असर होगा।

सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 12 मई को करेगा।

## पायलट खेमे के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मिलकर चलेंगे, सब मिलकर प्रयास सामूहिक प्रयास करेंगे, तब ही कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ सकती है।

पायलट समर्थक सोलंकी ने कहा कि पार्टी छोड़ने की बातें तो ऐसे ही चलती रहती हैं, लेकिन जिन लोगों से सरकार बन सकती है, जिनके चेहरे पर वोट मिलते हैं, उन लोगों को आगे लाना चाहिए। उन लोगों को जनता के सामने पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ''जनता सब जानती है। यह पब्लिक है, सब जानती है। समय पर सबका जवाब देती है, लेकिन वर्तमान समय में यह स्थिति है कि जिन लोगों के पीछे सरकार बनी थी, उन लोगों को आगे लाने का समय आ गया है। उन लोगों को आगे लाएं, मिलकर चलें, साथ चलें तभी सरकार दोबारा रिपीट कर सकते हैं।'' वेद प्रकाश सोलंकी ने शुक्रवार को राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की और उसके बाद यह बात मीडिया के सामने रखी।

इधर राजस्थान के नए सह प्रभारी बनाए गए वीरेंद्र सिंह राठौड़ में शुक्रवार को सचिन पायलट के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की हालांकि मुलाकात में क्या बात हुई इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। पायलट से मुलाकात करने के बाद राठौड़ देशनोक करणी माता के लिए रवाना हो गए।

# सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज

- **इससे पहले, इसी अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।**

नयी दिल्ली, 28 अप्रेल। दिल्ली शराब नीति-2021-22 में कथित अनियमितताओं में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामले में एक विशेष अदालत ने मनीलॉन्ड्रिंग के आरोपी आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

साउथ एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने ईडी के विरोध बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने 18 अप्रेल को जमानत याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, इसी अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 31 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां यह मामला लंबित है।

## 'यह कैसी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ग्रुप को हस्तांतरित करने के निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दें।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी. वाय चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की एक बैंच ने याचिकाकर्ता आशीष गिरी के इस मामले के पक्षकार बनने पर सवाल किया और कहा कि ''यह किस प्रकार की याचिका है और आप कौन हैं? आपके अनुरोध पर गौर नहीं किया जा सकता।''

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संदर्भ में ठाकरे और शिंदे गुटों की कई परस्पर विरोधी याचिकाओं पर गत 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चुनाव आयोग ने तीन कमान का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिया है तथा यह मुद्दा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

# पाकिस्तान में चुनाव की सुगबुगाहट

- **एक साल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बाद गठबंधन सरकार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रतिनिधि वार्ता की टेबल पर आए।**

इस्लामाबाद 28 अप्रेल। पाकिस्तान में चुनाव की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में एक साल की कड़वी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बाद गठबंधन सरकार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रतिनिधियों ने बैठक की। एक दिन पहले, सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने संघीय सरकार के अनुरोध पर सरकार के साथ बातचीत के लिए विपक्षी दल को एक मेज पर लाने का प्रयास किया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई प्रतिनिधि मंडल में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सीनेटर अली जफर शामिल थे, जबकि सरकार का प्रतिनिधित्व पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के इशाक डार, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तरार, सरदार अयाज सादिक और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) नेता यूसुफ रजा गिलानी और नवीद कमर ने किया था।

अंदरूनी सूत्रों ने डॉन को बताया कि, पीटीआई ने बैठक के दौरान तीन प्रमुख मांगें रखीं, जिसमें पहली मांग मई में नेशनल असेंबली और सिंध तथा बलूचिस्तान विधानसभाओं को भंग करके जुलाई में आम चुनाव का रास्ता साफ करना, दूसरी अगर सरकार पंजाब में 14 मई के चुनाव की तारीख से आगे जाना चाहती है, तो 90 दिनों से अधिक के मतदान में देरी के लिए एक बार की रियायत के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करना और पीटीआई एमएनए के इस्तीफे को नेशनल असेंबली में वापस लाने के लिए स्पीकर के आदेश को वापस लेना शामिल है।

## जम्मू में महिला...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

भी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए, बल्कि रात के समय महिलाओं, विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने तथा अकेले यात्रा करने वालों की सहायता करने के लिए भी तैनात किया गया है।

# कुश्ती फैडरेशन के मुखिया के...

- **इन प्लेयर्स ने यह भी कहा कि, उन्हें दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है तथा वे कमजोर सी धाराएं लगा सकते हैं, अतः वे तब तक धरने पर बैठेंगे, जब तक फैडरेशन के मुखिया हर सार्वजनिक पद से हटा नहीं दिये जाते।**
- **मुखिया ब्रज भूषण शरण सिंह छः बार भाजपा के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, गोण्डा, केसरगंज व बलरामपुर संसदीय सीट से।**
- **सिंह का पांच लोकसभा सीटों में भारी प्रभाव है और वे 2024 के चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।**

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

खिलाफ कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती। वे उत्तर प्रदेश के गौंडा, कैसरगंज तथा बलरामपुर सीटों से छः बार लोकसभा सांसद रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्य की पाँच लोकसभा सीटो पर सिंह का प्रभाव है तथा 2024 के चुनावों के लिये भाजपा के प्रचार की दृष्टि से वे अपरिहार्य समझे जाते हैं।

एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के निर्णय के समाचार पर प्रतिक्रिया देते हुये, सिंह ने कहा कि वे जानते थे कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होगी। उन्होंने आगे कहा, ''मैं इस बात को पूरी तरह हलका अनुभव कर रहा हूँ कि शीघ्र ही हर चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी। दिल्ली पुलिस को अपनी जाँच-पड़ताल करनी चाहिये। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जल्दी ही सच सामने आ जायेगा।''

आंदोलनकारी महिला पहलवानों में से एक, विनेश फोगट, जो भारत की मैडल-विजेता भी हैं, ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को एफ.आई.आर. दर्ज करने में छः दिन लग गये तथा पहलवानों को जाँच एजेंसी पर विश्वास नहीं है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैडलिस्ट ने कहा, ''पुलिस ढ़ीली या हल्की एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है। हम देखेंगे, परखेगे तथा उसके बाद आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लेंगे। वे (सिंह) उन सभी पदों से हटाये जाने चाहिए तथा उन्हें जेल भेजा जाना चाहिये, अन्यथा वे जाँच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।''

मुख्य न्यायाधिश डी.वाय. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की दो सदस्यीय बैंच के समक्ष उपस्थित होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि पहलवानों द्वारा दायर की गई याचिका को निपटा दें क्योंकि सिटी पुलिस आज बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने को तैयार हो गई है। अपनी शिकायत में, एक नाबालिग सहित, सात महिला पहलवानों ने सिंह पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

ओलिम्पिक में काँस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया तथा साक्षी मलिक एवं दो बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट रहीं विनेश फोगट, अन्य बहुत से पहलवानों के साथ रविवार से जन्तर मन्तर पर बैठे हुये है तथा माँग कर रहे हैं कि सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।

तीन महीने में यह दूसरा अवसर है, जब पहलवानों ने अपनी माँगों को लेकर दिल्ली में डेरा डाला है। जनवरी में, डब्ल्यू.एफ.आई. प्रमुख के खिलाफ यौन-उत्पीड़न एवं डराने-धमकाने के आरोपों की जांच के लिये, सरकार ने छः सदस्यीय पैनल गठित कर दिया था। इस पैनल ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किये हैं तथा कहा है कि अभी रिपोर्ट का निरीक्षण-परीक्षा चल रहा है।

# अमूल को ''साऊथवर्ड पुश''...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मालिक है, नन्दिनी का अधिग्रहण करता है तो उन लोगों की आजीविका खत्म हो जायेगी।

और फिर इसके बाद आता है उनका कन्नड़-गौरव, जिसका कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में बख़ूबी इस्तेमाल कर रही है। इस हवा का लाभ अब जनता दल (एस) के कुमारास्वामी भी उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने किसानों से वादा कर दिया है कि वे गुजरात के अमूल ब्रान्ड की लूटेरी कोशिशों से नन्दिनी को बचाने के लिये कुछ भी करने को तैयार हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने तो जनता से यहाँ तक कह दिया कि वे अमूल-उत्पादों का बहिष्कार कर दें, और तथ्य यह भी है कि कुछ होटलों और रेस्टोरेन्टों ने घोषणा तक कर दी है कि वे अमूल-उत्पाद नहीं खरीदेंगे।

भाजपा और कर्नाटक सरकार ने इस मुद्दे से जुड़े सभी दोषारोपणों का खण्डन किया है तथा कहा है कि वे नन्दिनी को संरक्षण प्रदान करेंगे तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के किसानों के अनुभव के चलते, कर्नाटक के किसानों को आशंका है कि अगर अमूल को खुली छूट दे दी गई तो वे कहीं के नहीं रहेंगे।

प्रसंगवश बता दें कि ऐसा प्रतीत होता हे कि आंध्र प्रदेश के घटनाक्रम से कर्नाटक के लोगों के डर एवं आशंकाओं को बल मिला है।

आंध्र प्रदेश के किसान संगठन अब आंध्र प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं तथा अमूल, जो वहाँ के स्थानीय सहकारी दुग्ध निकायों के खुशहाली को सीधे ही प्रभावित कर रहा है, की बेदखली की माँग कर रहे हैं। कृषक-ग्रुपों ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने पैसे से दूध खरीद कर अमूल को सप्लाई कर रही है। उनका यह आरोप भी है कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय सहकारी दुग्ध इकाइयों की कीमत पर अमूल को अपना व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की है। राज्य के पूर्व मंत्री वाड्डे सोभनेश्वर राव ने गुरुवार को विजयवाड़ा में आयोजित गोलमेज सभा को बताया कि अमूल के व्यवसाय से राज्य के किसी किसान को लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि स्थानीय सहकारी डेरियों की परिसम्पत्तियाँ अमूल को दी जा रही हैं।

पूर्व मंत्री ने कर्नाटक का उदाहरण भी दिया, जहाँ, वहाँ मच रही हाय-तौबा के बाद, सरकार को अमूल के साथ अपने दूध-कारोबार को निलम्बित करना पड़ा है।

इसके अतिरिक्त कर्नाटक में विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है तथा बासवराज बोम्मई को शीघ्र ही अपने कदम वापस लेने को बाध्य कर दिया है। इस बीच, अमूल ने भी एक बयान देकर कहा है कि वह कर्नाटक में अपने दुग्ध-व्यवसाय को फैलाने की कोशिश को निलम्बित कर रहा है। अमूल कर्नाटक मे दूध की खरीद-फरोख्त के व्यवसाय में प्रवेश करना चाहता था तथा स्थानीय किसान एवं व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं।

शीघ्र ही, इस मुद्दे को अपने लिये एक अच्छे अवसर के रूप में देखते हुये, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने बड़ी चतुराई के साथ इस सामान्य व्यावसायिक कोशिश को एक बहुत बड़े तथा प्रभावी चुनावी मुद्दे का रूप दे दिया तथा इस पूरे अभियान में कन्नड़-अस्मिता को भी खूबसूरत तरीके से गूँथ दिया।

प्रसंगवश बतादें कि कर्नाटक के दुग्ध-व्यवसाय में प्रवेश करने का अमूल का निर्णय उसके दक्षिण की तरफ बढ़ने (साउथवर्ड पुश) का हिस्सा है तथा इसकी प्रतिक्रिया के रूप में, स्थानीय लोकप्रिय सहकारी दुग्ध-ब्रान्ड कर्नाटक का ''नन्दिनी'', केरल का ''मिलमा'' तथा तमिलनाडु का ''आविन'' तथा अन्य निकाय अमूल की लूट का जवाब देने की कोशिशें के साथ आगे आने को बाध्य हो गये हैं।

राष्ट्रदूत ( एच.यू.एफ. ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908